



CH
11/7/86

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124]
No. 124]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 1986/ज्येष्ठ 10, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1986/JYAISTHA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1986

संकल्प

फा.सं. 11012/4/85-एम.आर. भारत सरकार ने, पंजाब के उन हिन्दी भाषा क्षेत्रों का निर्धारण और निश्चित करने के लिए जा चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को जाएंगे, अथवा दिनांक 2 अप्रैल, 1986 के संकल्प सं. 11012/4/85-एस. आर. के तहत एक आयोग नियुक्त किया जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री ई.एस. वेंकटरमैया थे।

2. चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को हस्तान्तरित किए जाने वाले गांवों के बारे में पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है। यह भी देखा गया है कि हरियाणा ने मूल दावा-विवरण में गांवों के बारे

में कोई तरजीह नहीं दी थी, और दावे की तरजह केवल 29-5-86 का नाम को तथा 30-5-86 को दी गई। इन परिस्थितियों में आयोग की अवधि की बढ़ाना आवश्यक हो गया है। तथापि इससे, समझौते के विवरण के अनुसार पंजाब राज्य को चंडीगढ़ का हस्तान्तरण करने में कोई बाधा नहीं आएगी एवं इसलिए भारत सरकार ने पंजाब को चंडीगढ़ का हस्तान्तरण 21 जून, 1986 को करने का निर्णय किया है। अतः चंडीगढ़ के हस्तान्तरण का, जैसा कि न्यायमूर्ति श्री वेंकटरमैया आयोग के गठन संबंधी संकल्प में कहा गया है, पालन हो जायेगा। सरकार ने आयोग की अवधि 10 जून, 1986 तक बढ़ाने का भी निर्णय किया है।

3. आयोग से अनुरोध है कि वह आयोग की बढ़ाई गई अवधि के दौरान पाटियों के संबंधित मामलों पर विचार करे।

4. इस संकल्प पर पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श कर लिया गया है।

आर.डी. प्रधान, सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेजी जाए, और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि आयोग को भेजी जाए।

आर. डी. प्रधान, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st May, 1986

RESOLUTION

F. No. 11012/4/85-S.R.—Government had vide its Resolution No. 11012/4/85-SR dated the 2nd April, 1986 appointed a Commission consisting of Shri Justice E. S. Venkataramiah, Judge of the Supreme Court of India to determine and specify the Hindi-speaking areas of Punjab which shall go to Haryana in lieu of Chandigarh.

2. There has not been an agreement between the Governments of Punjab and Haryana on the villages which could be transferred to Haryana in lieu of Chandigarh. It is also noticed that in the original claim statement, Haryana did not prefer any claim to the villages and preferred a claim only on the evening

of 29-5-86 and on 30-5-86. In the circumstances, it has become necessary to extend the term of the Commission. This, however, shall not come in the way of the transfer of Chandigarh to the State of Punjab in terms of the Memorandum of Settlement and the Government of India has, therefore, decided to transfer Chandigarh to Punjab on the 21st June, 1986. Thus the transfer of Chandigarh as envisaged in the Resolution constituting Shri Justice Venkataramiah Commission stands adhered to. The Government has also decided to extend the term of the Commission till 10th of June, 1986.

3. The Commission is requested to consider the respective cases of parties in due course during the extended period of the Commission.

4. This Resolution has been discussed with the Chief Ministers of Punjab and Haryana.

R. D. PRADHAN, Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India etc., and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to the Commission.

R. D. PRADHAN, Secy.